शुक्रवार
27 नवम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 306
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

कैबिनेट बैठक में 23 फैसलों पर लगी मुहर

आशाओं का मानदेय बढ़ा, वन आरक्षी भर्ती में उम्र की छूट



◆डॉक्टरों के लिए दो साल की अनिवार्य सेवा, चीनी मिलों को 207.75 करोड़ की बैंक गारंटी

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार ने कैबिनेट के फैसलों के जरिए कर्मचारी, श्रमिक, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1700 रुपये की वृद्धि, वन आरक्षी भर्ती में अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष करने और राजकीय मेडिकल कॉलेजों से पीजी करने वाले डॉक्टरों के लिए दो साल की अनिवार्य सेवा का प्रावधान प्रमुख हैं। वहीं, चीनी मिलों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार 207.75 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देगी। खनन क्षेत्र में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शुल्क दर पांच से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि रॉयल्टी की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई।

कैबिनेट बैठक में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा दायरे को बढ़ाने, सरकारी सेवाओं में नए पद सृजित करने और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। आशा कार्यकर्ताओं को अब प्रतिमाह 1700 रुपये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 8300 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। वहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधि कृत किया गया है।वन विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को भी राहत दी गई है। वन आरक्षी भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2028 तक अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (पीजी) करने वाले डॉक्टरों को पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राज्य में दो साल तक सेवाएं देनी होंगी। इसके लिए दो साल का सेवा अनुबंध अनिवार्य किया गया है।

श्रम विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके दायरे में अब संगठित क्षेत्र के साथ असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को भी शामिल किया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष गठित करने का भी निर्णय लिया गया है।कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत फार्मासिस्ट पद की सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता में संशोधन किया गया है। अब डी. फार्मा के साथ बी. फार्मा की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। उत्तराखंड एक्स-रे प्राविधिक सेवा संशोधन नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है।आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को गति देने के लिए सरकार ने चीनी मिलों को ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 207.75 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी देने पर सहमति जताई है। वहीं, आबकारी विभाग में उप आबकारी आयुक्त के पांच और सहायक आबकारी आयुक्त के छह नए पद सृजित किए जाएंगे। सेतु आयोग में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पदों को भी मंजूरी दी गई है।

शहरी परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हरिद्वार में 21.08 किलोमीटर लंबाई के तीन पीआरटी कॉरिडोर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इन कॉरिडोर में कुल 21 स्टेशन प्रस्तावित हैं। पहले कॉरिडोर की लंबाई 15 किलोमीटर होगी, जो सीतापुर से भारत माता मंदिर तक बनेगा। इससे हरिद्वार में यातायात का दबाव कम करने और जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।भवन निर्माण और बिल्डिंग बायलॉज के प्रावध ानों में शिथिलता देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्राधिकरण, यूडीए और शासन स्तर पर अनुमति की व्यवस्था होगी। राज्य में भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज) की दरों में भी करीब 25 प्रतिशत की कमी की गई है।

ऋषिकेश के बापूग्राम की 594 एकड़ आरक्षित वन भूमि सहित बिंदुखत्ता और अन्य वन क्षेत्रों में बसी आबादी को डी-नोटिफाई करने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अब राज्य सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी।इसके अलावा उत्तराखंड ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन और

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या

◆पिता ने लोहे के सरिये से बेटे का सिर फोड़ा!

हमारे संवाददाता

उधमसिंहनगर। रुद्रपुर में दो अलग-अलग घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी। पहली घटना में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवकों को रोकने पर एक सिक्योरिटी गार्ड की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि बीच-बचाव करने पहुंचे तीन अन्य लोग भी हमले में घायल हो गए। वहीं, दूसरी घटना में एक पिता ने अपने ही बेटे पर लोहे के सरिये से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. दोनों मामलों में पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के रेशमबाड़ी क्षेत्र में बीती शाम 50 वर्षीय लीलाधर पुत्र बिहारी लाल अपनी निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान घर के पास कुछ युवक शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि युवकों को हंगामा करने से रोकने पर विवाद शुरू हो गया। लीलाधर के भांजे राहुल पुत्र विजेंद्र पाल ने युवकों को हंगामा करने से मना किया। जिस पर आरोपियों ने राहुल के साथ मारपीट शुरू कर दी। भांजे को पिटता देख लीलाधर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करने लगे। आरोप है कि इस दौरान युवकों ने लीलाधर पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने राहुल के साथ ही रामअवतार पुत्र जौहरी लाल और अनुज पुत्र सुखदेव पर भी चाकू से वार किए। हमले में चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने सभी को तत्काल जिला



अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लीलाधर को मृत घोषित कर दिया। वहीं, राहुल, रामअवतार और अनुज का उपचार शुरू किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

रुद्रपुर की इंदिरा कॉलोनी में भी एक गंभीर वारदात सामने आई है। यहां एक पिता ने अपने बेटे पर लोहे के सरिये से हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। घटना 22 नवंबर की बताई जा रही है। इंदिरा कॉलोनी निवासी अनिल शादी-विवाह और अन्य कार्यक्रमों की एल्बम तैयार करने का काम करता है. आरोप है कि उसके पिता सुरेश ने किसी बात को लेकर अनिल पर लोहे के सरिये से हमला कर दिया। हमले में अनिल के सिर पर कई वार किए गए। जिससे उसके सिर में तीन गंभीर घाव हो गए। घायल अनिल को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कराया. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किए गए लोहे के सरिये को भी बरामद कर लिया है।

दून वैली मेल

संपादकीय

सत्ता का नया समीकरण

संसद का विशेष सत्र फिर चर्चा में है। सरकार इसे महत्वपूर्ण विधायी कामकाज से जोड़ रही है, लेकिन इसके केंद्र में महिला आरक्षण और परिसीमन का सवाल आते ही राजनीतिक बहस तेज हो गई है। सवाल यह है कि आखिर सरकार को इस मुद्दे पर इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्या महिला आरक्षण लागू करने की कोई निश्चित समयसीमा उसके पास है? यदि है तो उसे देश के सामने रखने में देरी क्यों? और यदि नहीं है तो फिर विशेष सत्र के जरिए किस राजनीतिक संदेश को स्थापित करने की कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए उन्हें और कितना इंतजार करना होगा? कानून बन चुका है, फिर भी महिलाओं को तत्काल राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि अगला लोकसभा चुनाव महिलाओं के आरक्षण के प्रावधान के साथ होगा? यदि ऐसा संभव नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या महिला आरक्षण फिर एक ऐसा चुनावी वादा बनकर रह जाएगा, जिसकी चर्चा हर चुनाव से पहले होगी और क्रियान्वयन की तारीख आगे खिसकती रहेगी? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि महिला आरक्षण और परिसीमन को एक-दूसरे से जोड़ना कितना अनिवार्य है? क्या महिला आरक्षण को लागू करने के लिए कोई वैकल्पिक संवैधानिक रास्ता नहीं है? यदि है तो उस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा? और यदि नहीं है तो सरकार देश को संवैधानिक बाध्यताओं का पूरा विवरण क्यों नहीं देती? लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की संभावनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सरकार ने सीटों के इस विस्तार का पूरा खाका तैयार कर लिया है? किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी? किस आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा? क्या इसका फार्मूला केवल जनसंख्या होगा या राज्यों के विकास, भौगोलिक परिस्थितियों और जनसंख्या नियंत्रण में उनके प्रदर्शन को भी महत्व मिलेगा? दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता को सरकार किस नजरिए से देख रही है? जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बेहतर काम किया, क्या उन्हें संसद में अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी कमजोर होने की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या प्रधानमंत्री यह भरोसा दे सकते हैं कि किसी भी राज्य के साथ जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल करने के कारण राजनीतिक अन्याय नहीं होगा? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि परिसीमन के बाद उत्तर और दक्षिण भारत के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संतुलन कैसे कायम रहेगा? क्या इस मुद्दे पर दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों से कोई औपचारिक संवाद हुआ है? क्या राज्यों को प्रस्तावित फार्मूले की जानकारी दी गई है? या फिर पहले फैसला तैयार होगा और बाद में राज्यों को उसे स्वीकार करने के लिए कहा जाएगा? उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए भी यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या केंद्र सरकार ने पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों, सीमांत गांवों, पलायन और बिखरी हुई आबादी को परिसीमन में विशेष महत्व देने का कोई प्रावधान तैयार किया है? क्या सरकार यह गारंटी देगी कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व केवल घटती आबादी के आंकड़ों के आधार पर कमजोर नहीं होगा? क्या प्रधानमंत्री को यह दिखाई देता है कि पहाड़ में गांव खाली हो रहे हैं, सीमांत क्षेत्रों में आबादी घट रही है और प्रतिनिधित्व का संकट गहराता जा रहा है? यदि परिसीमन में केवल जनसंख्या ही निर्णायक हुई तो क्या इसका सबसे बड़ा खामियाजा पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों को नहीं भुगतना पड़ेगा? आखिर देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले क्षेत्रों की राजनीतिक आवाज को केवल जनसंख्या के तराजू पर कैसे तौला जा सकता है? अप्रैल 2026 में संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई समर्थन नहीं मिल पाया था। सरकार विपक्ष पर जिम्मेदारी डाल सकती है, लेकिन क्या उसने सभी दलों की आशंकाओं को दूर करने का गंभीर प्रयास किया? क्या विधेयक लाने से पहले राज्यों और विपक्ष के साथ पर्याप्त चर्चा की गई? क्या इस बार सरकार कोई संशोधित और सर्वमान्य प्रस्ताव लेकर आ रही है? सरकार को यह भी बताना चाहिए कि क्या महिला आरक्षण पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वयं विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे? क्या विशेष सत्र केवल विधेयक पारित कराने की औपचारिकता होगा या देश के संघीय ढांचे पर व्यापक विमर्श का अवसर भी बनेगा? विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आपत्तियां स्पष्ट करे और महिला आरक्षण पर अपना रुख सार्वजनिक करे। लेकिन सरकार के पास सत्ता, संसाधन और विधायी पहल की जिम्मेदारी है। इसलिए जवाबदेही से वह बच नहीं सकती। एक और सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। क्या महिला सशक्तीकरण का अर्थ केवल संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देना है? देश में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक भागीदारी की वास्तविक स्थिति पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है? क्या राजनीतिक दलों में महिलाओं को टिकट देने और संगठन में नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने के लिए कोई ठोस व्यवस्था है? क्या सरकार अपने सहयोगी दलों और भाजपा के भीतर भी महिलाओं की भागीदारी का कोई स्पष्ट लक्ष्य तय करेगी? महिलाओं को अधिकार देने की बात करने वाली राजनीति को पहले अपने भीतर झांकना होगा। आखिर संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने का संकल्प रखने वाले दल अपने संगठन में महिलाओं को बराबरी का स्थान देने में कितने गंभीर हैं? विशेष सत्र में सरकार को कम से कम पांच सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए। महिला आरक्षण लागू करने की निश्चित तारीख क्या है? परिसीमन का आधार और फार्मूला क्या होगा? दक्षिण भारत और छोटे राज्यों के राजनीतिक हितों की रक्षा कैसे होगी? क्या विपक्ष और राज्यों से सहमति ली गई है? और क्या महिला आरक्षण को परिसीमन की प्रक्रिया से अलग तत्काल लागू करने का विकल्प मौजूद है? महिलाओं को आरक्षण चाहिए, राजनीतिक एहसान नहीं। राज्यों को न्याय चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण की सजा नहीं। और लोकतंत्र को पारदर्शिता चाहिए, सत्ता की सुविधा के मुताबिक तैयार किया गया गणित नहीं। प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को समझना होगा कि संविधान किसी एक दल की राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं है। संसद में बहुमत के आधार पर कानून बनाया जा सकता है, लेकिन देश के संघीय ढांचे में भरोसा केवल संवाद, सहमति और न्याय से ही कायम होगा। विशेष सत्र में सरकार को अपनी उपलब्धियां गिनाने से पहले इन सवालों के जवाब देने चाहिए।

न्याय की तलाश में परिवार की लड़ाई

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। चार साल पहले उत्तराखंड को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा हो चुकी है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन क्या अंकिता को पूरा न्याय मिल गया? इस सवाल का जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। जिस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था, उसकी सबसे संवेदनशील कड़ी यानी कथित वीआईपी का सवाल अब तक सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। नतीजा यह है कि मामला सुलझने के बजाय नए-नए मुकदमों, आरोपों, प्रत्यारोपों और जांच की अलग-अलग दिशाओं में उलझता जा रहा है।

18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वनंत्रा रिजार्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता भंडारी लापता हुई थी। छह दिन बाद 24 सितंबर को उसका शव चीला नहर से बरामद हुआ। इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया। रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की एसआईटी ने करीब 88 दिन की जांच के बाद लगभग 500 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया। 30 मई 2025 को पौड़ी की अदालत ने तीनों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कानूनी तौर पर यह हत्याकांड का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, लेकिन सामाजिक और सार्वजनिक स्तर पर उठे सवालों का अंत नहीं हुआ। अंकिता के परिवार और आंदोलनकारी संगठनों की मांग रही कि उस कथित वीआईपी की पहचान भी सामने आए, जिसके लिए अंकिता पर अतिरिक्त सेवाएं देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया था। परिवार का सवाल है कि क्या इस मामले में केवल तीन लोग ही शामिल थे या घटना के पीछे कोई और प्रभावशाली व्यक्ति भी था?

हत्याकांड के बाद से ही कथित वीआईपी का मुद्दा प्रदेश की राजनीति और सामाजिक आंदोलनों के केंद्र में रहा है। दिसंबर 2025 में अभिनेत्री उर्मिला सनावर

◆तीन आरोपियों को उम्रकैद, लेकिन वीआईपी का सवाल अब भी अनुत्तरित
◆सीबीआई जांच, आडियो-वीडियो की सत्यता, नार्को और पालीग्राफ टेस्ट
◆आठ मुकदमों और अब निजी चौट सार्वजनिक करने पर नई एफआईआर

ने कुछ आडियो और वीडियो रिकार्डिंग सार्वजनिक कीं। इनमें कथित तौर पर पूर्व विधायक सुरेश राठौर के साथ बातचीत का हवाला देते हुए वीआईपी का जिक्र किया गया। सनावर ने बाद में भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इस कथित वीआईपी के रूप में लिया। गौतम ने इन आरोपों को खारिज किया और कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति का नाम आरोपों में आने मात्र से उसकी संलिप्तता साबित नहीं होती। इन रिकार्डिंग के सामने आने के बाद मामला एक बार फिर गरमा गया। परिवार और सामाजिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच की मांग तेज की। जनवरी 2026 में प्रदेश सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की और सीबीआई ने कथित अज्ञात वीआईपी से जुड़े पहलू की जांच शुरू की।

लेकिन सवाल यह है कि चार साल बाद भी इस कथित वीआईपी की पहचान को लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो पाई? क्या जांच एजेंसी के पास पर्याप्त डिजिटल और अन्य साक्ष्य हैं? क्या आडियो-वीडियो रिकार्डिंग की प्रामाणिकता की जांच पूरी हुई है? क्या उन लोगों से पूछताछ हुई है, जिनके नाम इन रिकार्डिंग में सामने आए? इन सवालों के जवाब का इंतजार बना हुआ है। कथित वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने वाली उर्मिला सनावर भी अब इस पूरे प्रकरण में अलग-अलग मुकदमों और कानूनी विवादों में घिर गई हैं। अक्टूबर 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, उनके खिलाफ कम से कम आठ एफआईआर दर्ज थीं। इनमें छह एफआईआर दिसंबर 2025 में आडियो-वीडियो जारी करने के बाद दर्ज की गई थीं।

इस बीच सीबीआई ने उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नार्को और पॉलीग्राफ जांच के लिए सहमति देने संबंधी नोटिस जारी किए। दोनों ने अदालत के समक्ष इन परीक्षणों के लिए सहमति दी। 14 नवंबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून की अदालत ने सनावर के नार्को और पालीग्राफ परीक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था। लेकिन इससे पहले 25 अक्टूबर को उर्मिला सनावर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से उत्तराखंड पुलिस ने एक अलग एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तार कर

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'विकास में मैदान आगे, पहाड़ पीछे'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड बना था पहाड़ की पीड़ा दूर करने के लिए। सपना था कि पहाड़ के गांवों तक सड़क पहुंचेगी, खेतों में फिर हरियाली लौटेगी, युवाओं को अपने घर के पास रोजगार मिलेगा, अस्पतालों में इलाज होगा और बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए घर-बार छोड़कर मैदानों का रुख नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राज्य गठन के 26 साल बाद भी एक सवाल लगातार पीछा कर रहा है कि आखिर उत्तराखंड का विकास पहाड़ की बजाय मैदानों में ही क्यों सिमटता जा रहा है?

राज्य की विकास यात्रा का आकलन करें तो तस्वीर में दो उत्तराखंड दिखाई देते हैं। एक उत्तराखंड देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश, शहरीकरण, बेहतर सड़क नेटवर्क और आर्थिक गतिविधियों के साथ आगे बढ़ रहा है। दूसरा उत्तराखंड अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के गांवों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और पलायन की चुनौतियों से जूझ रहा है। यह अंतर केवल राजनीतिक आरोपों या क्षेत्रीय असंतोष की उपज नहीं है। सरकारी और संस्थागत रिपोर्टें भी पहाड़ और मैदान के बीच विकास की खाई की पुष्टि करती हैं।

पहाड़ और मैदान के बीच आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा प्रमाण प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों में दिखाई देता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के आधार पर मैदानी जिलों की औसत प्रति व्यक्ति आय 2,64,523 रुपये बताई गई है, जबकि दूरस्थ पर्वतीय जिलों में यह औसत महज 1,08,241 रुपये है। यानी मैदानी क्षेत्रों की औसत प्रति व्यक्ति आय पर्वतीय क्षेत्रों के

◆86 प्रतिशत भूभाग पहाड़ी, लेकिन विकास का बड़ा हिस्सा मैदानों में केंद्रित
◆सड़क, पेयजल, उद्योग, रोजगार और स्वास्थ्य सुविधाओं तक में गहरी खाई
◆पहाड़ के नाम पर अलग राज्य बना, मुख्यधारा में लाने का सपना है अधूरा

मुकाबले करीब ढाई गुने से अधिक है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में उद्योगों का विस्तार, देहरादून में सेवा क्षेत्र और शहरी अर्थव्यवस्था की मजबूती इस अंतर की बड़ी वजहों में शामिल हैं। दूसरी तरफ पहाड़ की अर्थव्यवस्था आज भी सीमित कृषि, छोटे कारोबार, सरकारी नौकरियों, पर्यटन और बाहर से आने वाली आमदनी पर काफी हद तक निर्भर है।

सवाल यह है कि जब राज्य का 86 प्रतिशत भूभाग पहाड़ी है तो विकास की आर्थिक गतिविधियों का इतना बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्रों में ही क्यों सिमटा हुआ है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के उत्तराखंड स्टेट फोकस पेपर 2023-24 में बुनियादी सुविधाओं के अंतर की तस्वीर सामने रखी गई है।

आज भी कई गांवों में सड़क पहुंचने के बाद भी स्वास्थ्य, शिक्षा और बाजार तक पहुंच आसान नहीं हुई है। बरसात में सड़कें बंद होती हैं, भूस्खलन से संपर्क टूटता है और मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पहाड़ के विकास की योजना बनाते समय उसकी भौगोलिक परिस्थितियों को पर्याप्त महत्व दिया गया? उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की कहानी मुख्य रूप से हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और देहरादून के आसपास केंद्रित रही है। सिडकुल और औद्योगिक क्षेत्रों ने इन इलाकों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। लेकिन पहाड़ में इस तरह के औद्योगिक अवसर विकसित नहीं हो सके।

इसका कारण केवल उद्योगपतियों की रुचि नहीं है। परिवहन लागत, बाजार से दूरी, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाएं, भूमि की उपलब्धता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता भी निवेश की राह में बाधा हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने पहाड़ की परिस्थितियों के अनुरूप उद्योग और रोजगार का कोई प्रभावी माडल विकसित किया? पर्वतीय क्षेत्रों में फल प्रसंस्करण, स्थानीय खाद्य उत्पाद, जड़ी-बूटी, दुग्ध उत्पादन, ऊन, हस्तशिल्प, रिंगाल और वन आधारित

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

राज्य स्तरीय बाल चौपाल का भव्य आयोजन

हमारे संवाददाता

देहरादून। कालसी विकासखंड द्वारा आज राज्य स्तरीय बाल चौपाल का आयोजन अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कालसी में किया गया। इस आयोजन में विकासखंड के 30 विद्यालयों के 600 से अधिक छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। लगभग 100 शिक्षकों ने कार्यक्रम में उपस्थित रहकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

कार्यक्रम में एससीईआरटी उत्तराखंड के अपर निदेशक पदमेन्द्र सकलानी, उप निदेशक विनोद मटुड़ा, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के राज्य प्रमुख शोभन सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी चकराता बुशरा, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सचिन असवाल, आदि ने भी बच्चों एवं शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया।

इस आयोजन की तैयारी शिक्षकों द्वारा एक सप्ताह से अधिक समय तक विद्यालय स्तर पर की गई। बच्चों की विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों को संचालित किया गया। वहीं विभिन्न स्टॉल पर गतिविधियों के अतिरिक्त भांति भांति के टीएलएम प्रदर्शित किये गए। दिमागी कसरत, आओ खेले खेल नए, आओ दौड़े भागें, मैं हूँ कलाकार जैसी तमाम थीम आधारित गतिविधियों में बच्चों और शिक्षकों ने खूब आनंद लिया।



समारोह में केजीबीवी कालसी एवं कोरुआ, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कालसी, एम आर बी स्कूल विकासनगर, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कालसी के बच्चों ने स्टॉल गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक रंगारंग प्रस्तुतियाँ भी दी। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस समारोह में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा शिक्षकों के साथ गतिविधियों व टीएलएम के निर्माण में सहयोग दिया गया। साथ ही विभिन्न संस्थाओं ने भी स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। जैसे भारत स्काउट गाइड, रूम टू रीड,आलभ्य फाउंडेशन, अमेरिका इण्डिया फाउंडेशन, आसरा ट्रस्ट, आदि। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण किया गया और प्रतिभाग करने वाले सभी बच्चों के लिए स्टेशनरी प्रदान की गई। गतिविधियों के संचालन में विभिन्न शिक्षकों, बीआरपी, सीआरपी, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने योगदान दिया। समारोह के अंत में खंड शिक्षा अधिकारी कालसी श्री भुवनेश्वर प्रसाद जदली ने इस आयोजन को सफल बनाने हेतु सभी का धन्यवाद दिया।

मंच संचालन मंगत राम, जगदीश एवं इश्मित द्वारा किया गया। समग्र रूप से यह आयोजन बच्चों के लिए सीखने, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने, नए अनुभव प्राप्त करने तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से व्यापक एक्सपोजर हासिल करने का एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। बाल चौपाल ने बच्चों को विद्यालय की सीमाओं से बाहर निकलकर आपसी सहभागिता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास एवं आनंदपूर्ण सीखने का मंच प्रदान किया।

ऋषिकेश मुख्य डाकघर की दीवार पर दिखेगी स्थानीय संस्कृति

नगर संवाददाता

ऋषिकेश। डाक विभाग की ओर से डाकघरों के नवीनीकरण के साथ-साथ स्थानीय कला, संस्कृति एवं विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष पहल की जा रही है। इसी क्रम में मुख्य डाकघर ऋषिकेश में स्थानीय सहभागिता के माध्यम से 'हमारी कहानी, डाक की जुबानी' थीम पर फीचर वॉल के डिजाइन एवं स्थापना के लिए प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उक्त जानकारी देते हुए पोस्ट मास्टर ऋषिकेश यू एस रावत ने बताया कि मुख्य डाकघर ऋषिकेश के नवीनीकरण का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसके तहत डाकघर की एक दीवार पर स्थानीय संस्कृति, कला एवं विरासत को दर्शाती आकर्षक पेंटिंग बनाई जानी है। इसके लिए स्थानीय कलाकारों एवं इच्छुक नागरिकों से पेंटिंग के प्रारूप आमंत्रित किए गए हैं। पोस्ट मास्टर रावत ने जानकारी देते हुए बताया प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति अपनी पेंटिंग का प्रारूप पूर्ण बायोडाटा के साथ 30 नवंबर 2026 तक जमा कर सकते हैं। चयनित डिजाइन को मुख्य डाकघर की दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही चयनित कलाकार को उसकी कलाकृति के लिए उचित प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी प्रावधान है।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

सिलक्यारा बचाव अभियान साहस, धैर्य और बेहतर समन्वय की ऐतिहासिक मिसाल : मुख्यमंत्री

◆प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की चार महत्वपूर्ण घोषणाएं



नगर संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय, देहरादून में प्रथम आपदा प्रबंधन दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से चार महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भूतपूर्व सैनिकों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, पुलिस तथा अन्य वर्दीधारी सेवाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों को आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके सहयोग से आम जनमानस को आपदाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रथम चरण में अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रति एक हजार विद्यार्थियों पर एक शिक्षक को राज्य सरकार द्वारा आपदा मित्र अथवा आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इनके माध्यम से छात्र-छात्राओं को आपदाओं के प्रति निरंतर जागरूक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आवासीय भवनों में किसी भी प्रकार की दुर्घटना के कारण आग लगने की घटना को आपदा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा ऐसे अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के मानकों के अनुरूप राहत राशि प्रदान की जाएगी। आपदाओं एवं सड़क दुर्घटनाओं के दौरान नि:स्वार्थ भाव से राहत एवं बचाव कार्यों में सहयोग करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) पुस्तिका एवं उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना (एसडीएमपी) 2026ख़ 27 का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन हमारे लिए निरंतर एक चुनौतीपूर्ण विषय है। प्रदेश को विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपदाओं के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ ही प्रत्येक स्तर पर पूर्व तैयारियों को मजबूत करना आवश्यक है। आपदा प्रबंधन से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को भी जोड़ा जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपदा की सूचना मिलते ही पूरा तंत्र सक्रिय हो और प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत एवं सहायता पहुंचे। कठिन परिस्थितियों में आपदा प्रभावितों के बीच जाकर उनके साथ खड़े रहना आवश्यक है। पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश ने अनेक आपदाओं का सामना किया है। इस दौरान शासन-प्रशासन तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने बेहतर समन्वय के साथ त्वरित राहत एवं बचाव कार्य किए हैं।

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि 12 नवंबर 2023 को दीपावली के दिन उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिक फंस गए थे। सभी श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने आपसी समन्वय के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री निरंतर बचाव अभियान की प्रगति की जानकारी लेते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की टीमों का भी अभियान में महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलक्यारा बचाव अभियान के दौरान अनेक तकनीकी चुनौतियां सामने आईं। श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए एक साथ विभिन्न वैकल्पिक उपायों पर कार्य किया गया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की सहायता ली गई। लगभग 17 दिनों के अथक प्रयासों के बाद 28 नवंबर 2023 को सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने में सफलता मिली। बाबा बौखनाग के आशीर्वाद, श्रमिकों के धैर्य, बचाव दलों के अथक परिश्रम तथा केंद्र एवं राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से यह अभियान सफल हुआ। मुख्यमंत्री ने भूकंप की दृष्टि से उत्तराखण्ड की संवेदनशीलता को देखते हुए भूकंप से बचाव के लिए भी मॉक ड्रिल आयोजित किए जाने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रिया तथा आपदा के बाद पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सिलक्यारा बचाव अभियान केवल एक सफल बचाव अभियान ही नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनशीलता का भी महत्वपूर्ण उदाहरण था। विषम परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना, जिला स्तर से लेकर भारत सरकार के स्तर तक बेहतर टीम वर्क तथा शीर्ष नेतृत्व द्वारा धरातल पर रहकर मार्गदर्शन प्रदान करना इस अभियान की सफलता के महत्वपूर्ण आधार रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि आपदा से प्रभावित अंतिम व्यक्ति तक समय पर सहायता पहुंचाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के प्रभावी उपयोग, प्रदेश में स्थित केंद्रीय संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ लेने, स्थानीय समुदायों की सहभागिता तथा विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन से जुड़े अनुभवों के व्यवस्थित दस्तावेजीकरण को भी आवश्यक बताया।

सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से सिलक्यारा बचाव अभियान, प्रदेश में आपदा प्रबंधन तंत्र के सुदृढ़ीकरण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, क्षमता विकास तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश में 133 क्यूआरटी गठित किए गए हैं, जिनमें 2250 सदस्य शामिल हैं। भूकंप की पूर्व चेतावनी के लिए 169 सेंसर एवं 112 सायरन स्थापित किए गए हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सतपाल महाराज, गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, खजान दास, प्रदीप बत्रा एवं श्री भरत सिंह चौधरी, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रुहेला एवं लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) रघुवीर सिंह भण्डारी, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ, सचिवगण तथा शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के सभी जिलाधिकारी तथा विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं भी जुड़े।

देहरादून साइक्लिंग क्लब ने साइकिलिस्टों को वितरित की संविधान की पुस्तकें



नगर संवाददाता

देहरादून। संविधान दिवस के अवसर पर देहरादून साइक्लिंग क्लब द्वारा अपने साइकिलिस्ट सदस्यों को भारतीय संविधान की पुस्तकें अपने ऑफिस में वितरित की गईं। इस पहल का उद्देश्य साइकिलिस्टों के बीच संवैधानिक जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें देश के संविधान, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है।

इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष हरिसिमरन सिंह ने कहा कि आज के समय में प्रत्येक नागरिक के लिए भारतीय संविधान को पढ़ना और समझना बेहद आवश्यक है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव और देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का मार्गदर्शक है। उन्होंने आगे कहा कि संविधान में नागरिकों को अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकारों की बात करते समय हमें अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के साथ-साथ अपने संवैधानिक एवं सामाजिक दायित्वों का भी पूरी ईमानदारी से निर्वहन करे।

क्लब द्वारा मोहम्मद हारिस, चित्रांग, विभव रंजन, वंश तोमर, वेदांश थापा, नमन रौतेला, हरनीक कौर, हिमांगी भाटिया, आदर्श रावत, प्रणय पंत एवं आर्यन चौहान को संविधान की पुस्तकें प्रदान की गईं।

क्लब अध्यक्ष ने बताया कि इस रविवार को देहरादून साइक्लिंग क्लब द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में थानगांव में विशेष साइकिल राइड आयोजित की जाएगी। इस राइड का उद्देश्य देहरादून के युवाओं के बीच संविधान के महत्व, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता फैलाना है। देहरादून साइक्लिंग क्लब का मानना है कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ नागरिक चेतना, संवैधानिक समझ और सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर ठगे डेढ लाख रुपये

संवाददाता

देहरादून। क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर खाते से निकाल डेढ लाख रूपये के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हीरा मार्केट वनखण्डी निवासी सिमरन उप्पल ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके फोन पर कॉल आयी और कॉल करने वाले ने उसका क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर जानकारी ली और उसके खाते से डेढ लाख रूपये निकाल लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

स्मैक के साथ दो गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने स्मैक के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासनगर कोतवाली पुलिस ने ढालीपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडा हुआ। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही दबोच लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से 6.56 ग्राम स्मैक बरामद कर ली। पूछताछ में उसने अपना नाम आरिफ पुत्र नाजर निवासी ढकरानी विकासनगर बताया। वहीं विकासनगर पुलिस ने बीडीएम स्कूल के पास से क व्यक्ति को 7.27 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। जिसने अपना नाम सूरज चौहान पुत्र सुभाष चौहान निवासी बालूवाला बताया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनको न्यायालय में पेश किया जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

उत्तराखंड में विकास नहीं, भ्रष्टाचार और अपराध ने पकड़ी रफ्तार: शरद जैन

नगर संवाददाता

देहरादून। आम आदमी पार्टी के नेता शरद जैन ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों में 20 प्रमुख क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास और चुनावी घोषणापत्र के वादों को पूरा करने के दावे पर तीखा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आंकड़ों, विज्ञापनों, निवेश सम्मेलनों और बड़े-बड़े दावों के माध्यम से जनता को विकास की तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रही है, लेकिन प्रदेश की वास्तविकता इन दावों से बिल्कुल अलग है।

शरद जैन ने कहा कि यदि भाजपा सरकार ने वास्तव में पिछले दस वर्षों में उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास किया है, तो उसे प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में कितना सुधार हुआ? कितने सरकारी स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक, आधुनिक प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? आज भी अनेक सरकारी विद्यालय बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार शिक्षा नीति लागू करने का श्रेय तो ले रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और आधारभूत ढांचे की स्थिति पर जवाब देने से बच रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान कार्ड और करोड़ों रुपये के उपचार का आंकड़ा तो प्रस्तुत कर रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी, खाली पद, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों का अभाव और स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाल स्थिति पर मौन है। सवाल यह है कि यदि अस्पतालों में डॉक्टर और मशीनें ही उपलब्ध नहीं हैं, तो आम गरीब व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण इलाज कैसे मिलेगा? बळ की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर फरवरी 2025 में सदन में प्रस्तुत प्रदर्शन ऑडिट रिपोर्ट भी सरकार के स्वास्थ्य संबंधी दावों की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता को दर्शाती है।

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर शरद जैन ने कहा कि महिला सशक्तीकरण केवल लखपति दीदी बनाने, आरक्षण देने और स्वयं सहायता समूहों के आंकड़े गिनाने से नहीं होता। महिला सशक्तीकरण का वास्तविक अर्थ है महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, सम्मान, न्याय और आर्थिक स्वतंत्रता देना। प्रदेश में हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाएं लगातार गंभीर चिंता का विषय बनी हुई हैं। छब्ठ के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में उत्तराखंड में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 3,342 मामले दर्ज हुए। सरकार को बताना चाहिए कि महिला सुरक्षा के लिए कितने प्रभावी कदम उठाए गए और पीड़ितों को समय पर न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है?

किसानों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि मंडुवा, झंगोरा, कीवी और ड्रैगन फ्रूट की नीतियों तथा सब्सिडी का प्रचार करना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि पिछले दस वर्षों में एक सामान्य किसान की वास्तविक आय कितनी बढ़ी? कितने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिला? कितने किसानों की फसल का समय पर भुगतान हुआ? कितने गांवों में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था हुई? पहाड़ों से खेती छोड़कर पलायन करने वाले किसानों की संख्या में कितनी कमी आई? भाजपा सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।

शरद जैन ने कहा कि भाजपा के 2022 के दृष्टि पत्र में किए गए कई बड़े वादों पर भी सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए। भाजपा सरकार को इन वादों पर केवल भाषण नहीं, बल्कि विभागवार उपलब्धि, बजट खर्च, लाभार्थियों और धरातलीय परिणामों का प्रमाण देना चाहिए।

शरद जैन ने कहा कि जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय और बजट में वृद्धि के आंकड़े प्रस्तुत करना आसान है, लेकिन आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक पहुंचा या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यदि राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो आम परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार क्यों नहीं दिख रहा? युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जा रहे हैं? पहाड़ों के गांव खाली क्यों हो रहे हैं? सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर जनता का भरोसा क्यों कम हो रहा है?

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के पिछले दस वर्षों में यदि किसी क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है तो वह भ्रष्टाचार, सत्ता के संरक्षण में अनियमितताओं और अपराधों को लेकर जनता की बढ़ती चिंताओं का क्षेत्र है। जनता के सामने असली सवाल यही है कि विकास किसका हुआख्रआम जनता का या सत्ता में बैठे लोगों का?

शरद जैन ने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह 20 सेक्टरों की उपलब्धियों का प्रचार करने से पहले हर सेक्टर का स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट कराए और जनता के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसान आय, पलायन तथा भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र जारी करे। उत्तराखंड की जनता को कागजी विकास नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। अब जनता विज्ञापनों से नहीं, अपने जीवन में आए बदलाव से सरकार का मूल्यांकन करेगी।

शब्द सामर्थ्य -81

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :

1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्कीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे

1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 8. पेड़ का धड़ा जहां से शाखाएं निकलती है, 9. मिठाई, खाने की मीठी चीज 12. शासन, गुप्तबात 13. श्रद्धा, स्त्री, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य 15. विपत्तिग्रस्त, दुखी, अभागा 16. प्रसिद्ध, नामवर 18. स्वप्न, ख्वाब 20. करीब, नज़दीक, समीप 21. सुबह, प्रातः, सबेरा।

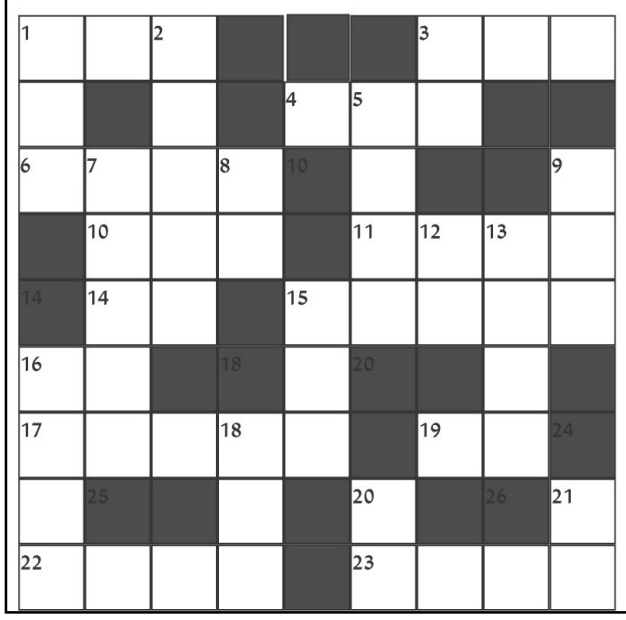

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 80 का हल

अ	भि	षे	क	■	प	स	■	■
जा	त	■	थ	प	थ	पा	ना	■
य	र	का	नी	■	भ्र	■	र	श्मि
ब	घा	र	■	क	ष्ट	प्र	द	■
■	त	ना	त	नी	■	र्व	■	ब
अ	■	मा	■	ज	मा	त	■	ल
स	जा	■	■	■	■	क	ज	रा
बा	■	बे	स	हा	रा	■	ग	म
ब	गु	ला	■	रा	ज	दू	त	■

हनु-मान के बाद अब आएगी हनुमान 2 - द राइज ऑफ वानरास, सामने आया धमाकेदार पोस्टर

ब्लॉकबस्टर फिल्म हनु-मान के मेकर्स ने शनिवार को हनुमान 2 – द राइज ऑफ वानरास की घोषणा कर दी है। यह फिल्म लोकप्रिय हनु-मान यूनिवर्स का अगला चैप्टर होगा। हनुमान 2 – द राइज ऑफ वानरास की घोषणा करते हुए मेकर्स ने बताया कि इसमें अभिनेता वैष्णव तेज फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। प्रोडक्शन हाउस प्राइमशो एंटरटेनमेंट ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर शेयर किया, जिसमें रहस्यमयी दुनिया की एक झलक देखने को मिलती है। बादलों के बीच से ऊपर उठते एक दमदार सीन दिखाई देता है, जिसके चारों ओर एक विशाल दिव्य पूंछ और एक अलौकिक दिव्य उपस्थिति है। इस विजुअल ने फिल्म से उम्मीदें भी बढ़ा दी हैं।



पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, जो एक सपने के साथ शुरू हुआ था, वह अब और भी बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। हनु-मान की विरासत को अपने अगले महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ आगे ले जाने पर गर्व है। पेश है, हनुमान 2 – द राइज ऑफ वानरास। अभिनेता वैष्णव तेज फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। आपको जल्द ही हम नया अपडेट देंगे।

एक भव्य फैंटेसी एंटरटेनर के रूप में पेश की गई यह फिल्म, पौराणिक कथाओं, कल्पना और असाधारण सिनेमाई संभावनाओं से जुड़ी एक आकर्षक नई दुनिया के दरवाजे खोलेगी। इस फिल्म को वी. आनंद ने लिखा और निर्देशित किया है, जबकि इसका निर्माण के. निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी कर रहे हैं।

के. निरंजन रेड्डी और चैतन्य रेड्डी इस फिल्म को प्राइमशो एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस कर रहे हैं। ब्लॉकबस्टर हनु-मान देने के बाद, प्रोड्यूसर्स फिलहाल मेगा सुप्रीम हीरो साई दुर्गा तेज के साथ एसवाईजी और किच्चा सुदीप के साथ बीआरबी बना रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि यह नई फिल्म प्रोड्यूसर्स की ओर से एक और महत्वाकांक्षी सिनेमाई प्रोजेक्ट होगी, जिन्हें दर्शकों के लिए एक शानदार सिनेमाई अनुभव बनाने के लिए जाना जाता है। यह फिल्म तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़, इन पांच भाषाओं में रिलीज होगी।

मुंबई के लोग मदद के लिए तुरंत आते हैं आगे : माधुरी दीक्षित

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के मराठी क्विज शो कौन होणार करोड़पति में अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर भुवन बाम गेस्ट के तौर पर शिरकत हुए थे। इस दौरान अभिनेत्री ने मुंबई शहर के प्रति अपने लगाव पर बात की। अभिनेत्री और भुवन बाम ने मुंबई के लिए अपने प्यार पर बात की, इस दौरान माधुरी दीक्षित ने मुंबई की खूबी पर प्रकाश डाला, जो उनकी नजर में मुंबईकरों को सबसे अलग बनाती है।

अभिनेत्री ने बताया कि मुंबई के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं और हमेशा अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। शो के दौरान माधुरी दीक्षित अभिनेता भुवन बाम से पूछती हैं, आपको मुंबई में क्या पसंद हैं? , भुवन बाम कहते हैं, यहां के लोग। माधुरी दीक्षित भुवन बाम की बात से सहमती जताते हुए कहती हैं, यहां के लोग मदद के लिए तुरंत आगे आते हैं और यहां बहुत अपनापन है। भुवन तुरंत उनकी बात से सहमत हो गए और बोले, सौ प्रतिशत। इसके बाद माधुरी ने सीटी बजाई और मुंबईकरों को सलाम करते हुए अपना हाथ उठाया।

बता दें कि माधुरी दीक्षित का पालन-पोषण मुंबई में ही हुआ है और उनका बचपन शहर के अंधेरी इलाके में बीता है। बाद में उन्होंने विले पार्ले में कॉलेज की पढ़ाई की और फिर बॉलीवुड में अपना करियर बनाया।

शादी के बाद माधुरी अमेरिका चली गईं और अपने बच्चों की परवरिश के दौरान कई साल तक मुंबई से दूर रहीं। बाद में वह वापस शहर लौट आईं और भारतीय मनोरंजन जगत में अपने पेशेवर सफर को फिर से शुरू किया। मराठी सिनेमा के साथ माधुरी दीक्षित के जुड़ाव की बात करें तो उन्होंने बकेट लिस्ट से मराठी फिल्मों में डेब्यू किया था और तब से मराठी सिनेमा के साथ उनका जुड़ाव और मजबूत होता गया है।

उन्होंने अपने पति डॉ. श्रीराम नेने के साथ प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया और 15 अगस्त और पंचक जैसे प्रोजेक्ट्स को बैक किया। वह एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर के तौर पर हिंदी और मराठी सिनेमा में लगातार सक्रिय हैं।

'अपनों' से टिकट के लिए 'जंग'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की जंग अभी मैदान में उतरनी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के भीतर इसकी शुरुआत हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में टिकट की दावेदारी ने नेताओं को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। पार्टी के भीतर ही एक-दूसरे की राजनीतिक जमीन नापी जा रही है। कोई वर्षों की संगठनात्मक मेहनत का हवाला देकर टिकट मांग रहा है तो कोई क्षेत्र में अपनी पकड़ और जनाधार का दावा कर रहा है। मौजूदा विधायक अपनी सीट बचाने की कोशिश में हैं तो नए दावेदार उन्हें चुनौती देने के लिए सक्रिय हो चुके हैं। राजनीति का यह दिलचस्प पहलू है कि चुनाव से पहले दोनों दलों के नेता विपक्ष से मुकाबले की तैयारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन टिकट की बारी आते ही सबसे बड़ी चुनौती अपने ही कुनबे को संभालने की बनती दिखाई दे रही है। एक सीट पर कई दावेदारों की मौजूदगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि किसे मौका दिया जाए और किसे नाराजगी के बावजूद संगठन के साथ बनाए रखा जाए।

भाजपा में टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा केवल नए और पुराने चेहरों के बीच नहीं है, बल्कि मौजूदा विधायकों के सामने भी पार्टी के भीतर से चुनौती खड़ी हो रही है। पार्टी नेतृत्व विधायकों के कामकाज, क्षेत्र में सक्रियता और बूथ स्तर से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर उनकी दावेदारी परखने की बात कर रहा है। ऐसे में जिन सीटों पर कई दावेदार हैं, वहां टिकट का फैसला आसान नहीं रहने वाला। कुमाऊं में भी दावेदारी का यही दौर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी, कालाढूंगी, लालकुआं और रामनगर जैसी सीटों पर मौजूदा विधायकों के साथ पूर्व जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकारी और नए चेहरे भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या दस से अधिक बताई जा रही है।

भाजपा की तरह कांग्रेस में भी टिकट की लड़ाई ने अंदरूनी समीकरणों को गर्म कर दिया है। पार्टी के सामने एक ओर सत्ता में वापसी की चुनौती है, दूसरी ओर वरिष्ठ नेताओं, पुराने प्रत्याशियों और नए दावेदारों के बीच तालमेल बैठाने की परीक्षा है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं के अपने-अपने राजनीतिक समर्थक आधार हैं। ऐसे में टिकट वितरण के दौरान सभी गुटों और क्षेत्रीय समीकरणों को साधना नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है।



◆भाजपा और कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की है लंबी कतार
◆कहीं मौजूदा को चुनौती व पुराने दिग्गजों के सामने नए चेहरे
◆टिकट से पहले ही दोनों दलों में बढ़ने लगी है अब खींचतान

दोनों दलों में टिकट की लड़ाई का एक बड़ा पहलू पीढ़ीगत बदलाव भी है। भाजपा संगठन में युवाओं को आगे लाने और नए चेहरों को अवसर देने की बात कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी युवाओं को विधानसभा तक पहुंचाने की मंशा जता चुके हैं। लेकिन नए चेहरों को जगह देने का अर्थ कई सीटों पर मौजूदा विधायकों या लंबे समय से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे नेताओं की दावेदारी प्रभावित होना भी है। कांग्रेस में भी नए चेहरों को मौका देने की चर्चा है, लेकिन वहां वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक भूमिका, उनके समर्थकों की अपेक्षाएं और स्थानीय स्तर पर सक्रिय दावेदारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। टिकट के लिए सर्वे और संगठनात्मक फीडबैक की बात अपनी जगह है, लेकिन अंतिम निर्णय के समय राजनीतिक समीकरण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा सवाल केवल प्रत्याशी चुनने का नहीं, बल्कि टिकट से वंचित नेताओं को साथ बनाए रखने का भी है। चुनाव में एक टिकट के लिए कई नेता दावेदारी करते हैं, लेकिन अंततः किसी एक को ही उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ऐसे में बाकी दावेदारों की नाराजगी को संभालना नेतृत्व की असली परीक्षा होगी। उत्तराखंड की राजनीति में टिकट कटने के बाद बगावत, निर्दलीय चुनाव लड़ने और दूसरे दलों का रुख करने की घटनाएं नई नहीं हैं। इस बार भी यदि किसी प्रभावशाली दावेदार को नजरअंदाज किया गया तो वह पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा कर सकता है। सार्वजनिक रूप से संगठन के फैसले को स्वीकार करने की बात कहने वाले नेता भी चुनाव के समय कितनी सक्रियता से अधिकृत प्रत्याशी के साथ खड़े होंगे, यह अलग सवाल है। भाजपा के सामने सत्ता में रहते हुए विधायकों के प्रदर्शन और नए चेहरों की मांग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने सत्ता में वापसी की तैयारी के साथ अपने वरिष्ठ नेताओं और स्थानीय दावेदारों को एक मंच पर रखने की जिम्मेदारी है।

फिलहाल दोनों दलों में टिकट की दावेदारी ने चुनावी राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सवाल चुनाव का हिस्सा बाद में बनेंगे, लेकिन उससे पहले पार्टियों के भीतर टिकट का सवाल सबसे बड़ा बनता जा रहा है। असली परीक्षा यह होगी कि टिकट की जंग में एक-दूसरे को चुनौती दे रहे नेता फैसला आने के बाद कितनी सहजता से एक ही झंडे के नीचे खड़े होते हैं। क्योंकि चुनाव में मुकाबला विपक्ष से होता है, लेकिन टिकट की लड़ाई में सबसे पहले अपने ही सामने खड़े दिखाई देते हैं।

हल्द्वानी के 21 केंद्रों में होगी पीसीएस परीक्षा, धारा 163 लागू

हल्द्वानी(आरएनएस)। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (पीसीएस) प्रारंभिक परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए हल्द्वानी के 21 परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि 29 नवंबर को परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर दो से शाम चार बजे तक होगी। परीक्षा के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है। आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में पांच या अधिक लोगों के समूह में एकत्र होने और सार्वजनिक सभा करने पर रोक रहेगी। परीक्षार्थी या अन्य व्यक्ति शस्त्र, लाठी, डंडा आदि लेकर नहीं पहुंच सकेंगे। केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। अफवाह फैलाने और पर्चे वितरित करने पर भी रोक लगाई गई है।

जमीन के नाम पर ठगे 35 लाख रुपये

संवाददाता

देहरादून। जमीन दिलाने के नाम पर 35 लाख रूपये की ठगी के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आईटीबीपी निवासी विजय कुन्डु ने पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पहचान अंकित मलिक निवासी दून एन्क्लेव शिमला बाईपास से हुई थी। उसने उसको चन्द्रबनी में एक जमीन दिखायी उसको वह पसंद आ गयी और उसने अंकित को 35 लाख रूपये बयाने के तौर पर दे दिये। लेकिन उसके बाद अंकित ने न तो उसके नाम रजिस्ट्री करायी और न ही उस के रूपये वापस किये। पैसे मांगने पर उसके साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी दी।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

फोन कर क्रेडिट कार्ड से निकाले साढे तीन लाख रुपये

संवाददाता

देहरादून। फोन कर क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर खाते से साढे तीन लाख रूपये निकाल लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अधोईवाला निवासी मौहम्मद अयान ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उ सके फोन पर एक कॉल आयी और कॉल करने वाले ने उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर उसके खाते से साढे तीन लाख रूपये निकाल लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

कलियासौड़ क्षेत्र में एनएच से हटेंगे अतिक्रमण, नोटिस जारी

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। राष्ट्रीय राजमार्ग को अतिक्रमणमुक्त बनाने की दिशा में एनएच डिवीजन श्रीनगर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके तहत कलियासौड़ स्थित धारी देवी मंदिर के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे से दस अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। विभाग ने संबंधित अतिक्रमणकारियों को प्रथम चरण में नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण स्वयं हटाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।एनएच डिवीजन श्रीनगर की सहायक अभियंता गर्विता पांडे ने बताया कि धारी देवी मंदिर के ऊपर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दस अतिक्रमण चिह्नित किए गए हैं। विभाग की ओर से सभी संबंधित लोगों को पहला नोटिस जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम नोटिस के बाद दो और नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बावजूद यदि संबंधित लोग निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाते हैं तो विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण से बाधित भी होता है। ऐसे में चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने के लिए नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रीनगर के शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिलहाल कोई अतिक्रमण चिह्नित नहीं किया गया है। शहरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर केवल रैंप बने हुए हैं।

चोपता बाजार में घंटों लग रहा जाम

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। तल्लानागपुर के मुख्य बाजार चोपता में इन दिनों यातायात व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। यहां घंटों तक लगने वाला जाम लग रहा है। वाहनों की लंबी कतारें लगने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानियों हो रही है। यातायात व्यवस्था होमगार्ड के भरोसे संचालित है। इससे कार्तिक स्वामी पहुंचने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों व स्थानीय लोगों को दिक्कते हो रही है। यहां दर्जनों गांवों के लोग दैनिक कार्यों के लिए आते है। यातायात व्यवस्था को होमगार्ड के जवान नियंत्रित करने के प्रयास करते है।जाम से कार्तिक स्वामी मंदिर जाने वाले श्रद्धालु घंटों जाम खुलने का इंतजार करते है। क्षेत्र पंचायत सदस्य फलासी दिनेश सिंह नेगी ने बताया कि घंटों तक जाम लगने से स्थानीय जनता, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों को परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चोपता में यातायात व्यवस्था के लिए नियमित पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग की है। व्यापारी मानवेन्द्र सजवाण ने कहा कि जाम की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। यातायात व्यवस्था केवल होमगार्ड के भरोसे छोड़ने से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने की मांग की। व्यापारी विनोद जगवाण बताया कि यदि समय रहते चोपता की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो आने वाले समय में वाहनों का बढ़ता दबाव स्थानीय जनता के साथ ही तीर्थाटन एवं पर्यटन के लिए चुनौती बन सकता है।

सू- दोकू क्र. 81

	2		6		8		3	
9		8		3		4		
							5	
5		2			7		6	
	8		4			1		3
				9				
8			9				1	
	5			1		6		2
		1	7				4	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.80 का हल

2	6	3	8	1	4	9	7	5
9	5	4	2	6	7	3	1	8
8	7	1	9	3	5		6	2
6	2	7	5	4	8	4	3	9
3	9	8	6	7	1	2	5	4
4	1	5	3	2	9	6	8	7
5	3	2	4	8	6	7	9	1
1	8	6	7	9	2	5	4	3
7	4	9	1	5	3	8	2	6

अल्मोड़ा दुग्ध संघ की प्रबंध कमेटी भंग, पुनर्गठन तक सीडीओ संभालेंगे जिम्मेदारी

अल्मोड़ा(आरएनएस)। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अल्मोड़ा की प्रबंध समिति में नौ निर्वाचित सदस्यों में से छह के अनर्ह पाए जाने के बाद समिति के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। छह सदस्यों के अनर्ह होने से समिति में केवल तीन सदस्य ही अर्ह रह गए हैं, जबकि वैधानिक रूप से आवश्यक न्यूनतम संख्या पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में समिति के पुनर्गठन तक संघ के कामकाज की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रशासक के रूप में सौंपी गई है।

दुग्ध सहकारी समितियां उत्तराखंड की निदेशक एवं निबंधक इला गिरी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि संघ की वर्तमान प्रबंध समिति के छह निर्वाचित सदस्य विभिन्न वैधानिक एवं उपविधिक प्रावधानों के तहत अनर्ह पाए गए हैं। आदेश के अनुसार संबंधित प्राथमिक दुग्ध समितियों के कार्यकाल, निर्धारित दुग्ध प्रदाय की मात्रा एवं दिनों के मानकों को पूरा न करने, निर्वाचन संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं होने तथा अन्य वैधानिक प्रावधानों के आधार पर सदस्यों की अर्हता का परीक्षण किया गया। जांच और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर छह सदस्यों को अनर्ह पाया गया। संबंधित सदस्यों को अपना पक्ष रखने के लिए सुनवाई का अवसर भी दिया गया था।

प्रकरण में दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश चन्द्र खोलिया की ओर से भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। आदेश में उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई, संबंधित अधिकारियों से प्राप्त आख्या और सदस्यों की अर्हता से जुड़े अभिलेखों का भी उल्लेख किया गया है। आदेश में कहा गया है कि छह सदस्यों के अनर्ह होने के बाद प्रबंध समिति में केवल तीन सदस्य अर्ह रह गए हैं। निर्धारित न्यूनतम वैधानिक संख्या पूरी नहीं होने के कारण वर्तमान प्रबंध समिति संघ के कार्यों और दायित्वों का प्रभावी संचालन करने की स्थिति में नहीं है। इसे देखते हुए उत्तराखंड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 की धारा 29(5)(ख) के तहत प्रबंध समिति के पुनर्गठन तक संघ के कार्यों का संचालन करने के लिए मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा को प्रशासक नियुक्त किया गया है। अब प्रबंध समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी होने तक संघ का प्रशासनिक कामकाज प्रशासक के स्तर से संचालित होगा। आदेश की प्रतियां संबंधित विभागीय अधिकारियों, जिला प्रशासन और दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड अल्मोड़ा के प्रधान प्रबंधक/सचिव को भी भेजी गई हैं।

चमोली जिले में आठ स्थानों पर मॉक ड्रिल कल

चमोली(आरएनएस)। चमोली जिले में 28 नवंबर को जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन का वृहद मॉक अभ्यास किया जाएगा। इसके तहत जिले के आठ स्थानों पर अलग-अलग आपदाओं की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कर तैयारियों को परखा जाएगा।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंद किशोर जोशी ने बताया कि विभिन्न विभागों की तैयारियों, आपसी समन्वय और आपात स्थिति में त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों की क्षमता जांचने के लिए यह अभ्यास किया जा रहा है। इसके अलावा जीआईसी थराली में भूकंप, नंदानगर में हेलिकॉप्टर लैंडिंग और गैरसैंण के कालीमाटी में वनाग्नि की घटना से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। मॉक अभ्यास सुबह नौ बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक चलेगा। इसमें संबंधित विभागों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों की तत्परता, संसाधनों की उपलब्धता और आपसी समन्वय को परखा जाएगा।

बेस अस्पताल के लिए सभी एक होकर करें प्रयास

चमोली(आरएनएस)। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सिमली बेस अस्पताल के लिए बनी समिति के पदाधिकारियों और समिति के पदाधिकारियों की आपसी समन्वय बैठक हुई।

बैठक में बेस अस्पताल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सिमली बेस के लिए जीओ जारी करने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि समिति के पदाधिकारियों को एक होकर सिमली बेस अस्पताल के लिए पहल करनी चाहिए।

बृहस्पतिवार को आयोजित बैठक में विधायक अनिल नौटियाल, जिपंस विक्रम कठैत, समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी सहित कमेटी के सदस्य शामिल हुए। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांच सदस्यीय कमेटी बनाकर इसका हल निकालने की बात कही थी। अब इस दिशा में सकारात्मक पहल करने के लिए संघर्ष समिति के साथ विचार विमर्श कर उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजने की पहल की जाएगी।

जिपंस विक्रम कठैत ने कहा कि संघर्ष समिति की ओर से की जा रही मांग न्याय संगत है। बेस अस्पताल संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि समिति के पदाधिकारियों और आम जन मानस से वार्ता करने के बाद महिला बेस अस्पताल सिमली को पूर्ण बेस अस्पताल का शासनादेश जारी करने और सीएम की घोषणा के अनुरूप मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजकर एक सप्ताह में जीओ जारी करने की पहल करने पर ही सकारात्मक वार्ता मानी जाएगी।

बैठक में समिति के संरक्षक महेश डिमरी, उपाध्यक्ष बीएन डिमरी, संतोषी कनवासी, कपीरी संघर्ष समिति के अध्यक्ष खिलदेव रावत, महेश चंद्र, रणधीर सिंह पुंडीर, सुनीता देवी, सोहन सिंह आदि ने विचार व्यक्त किए।

जिला स्तरीय क्विज और निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई प्रतिभा

अल्मोड़ा(आरएनएस)। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय और जिला स्वीप टीम की ओर से निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से पीएम श्री अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में जिला स्तरीय निबंध एवं क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें जिले की छह विधानसभा क्षेत्रों से चयनित छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग कर निर्वाचन संबंधी ज्ञान और लोकतांत्रिक जागरूकता का परिचय दिया।

कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में मतदाता जागरूकता, लोकतांत्रिक मूल्यों, निर्वाचन प्रक्रिया और जिम्मेदार नागरिकता की समझ विकसित करना रहा। क्विज प्रतियोगिता डिजिटल माध्यम से आयोजित की गई, जिसे जिला स्वीप टीम के सदस्य पंकज जोशी ने तैयार किया था। क्विज में अल्मोड़ा विधानसभा की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम में राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के मनीष लोहानी, सौम्या जोशी और गीतिका पांडे तथा राजकीय इंटर कॉलेज पेटशाल के हर्षित टम्टा शामिल रहे। रानीखेत विधानसभा की टीम द्वितीय और सल्ट विधानसभा की टीम तृतीय स्थान पर रही।

रानीखेत की टीम में शिवानी, दिया करायत, यामिनी आर्या और लक्ष्मी देव तथा सल्ट की टीम में विशाल बिष्ट, गौरव सिंह नेगी और मुकुल सत्यवाली शामिल रहे। निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने %शुद्ध मतदाता सूची का महत्व% और %मतदान का महत्व% विषय पर विचार प्रस्तुत किए। इसमें कल्पना जलाल, कंचना आर्या, रितिका बठकोटी, मानसी मेर और शिवानी सहित 10 प्रतिभागियों का चयन किया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी हरक राम कोहली ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों पर निर्भर करती है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं जागरूक मतदाता बनने और परिवार व समाज में भी मतदाता जागरूकता का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा के प्रधानाचार्य राजेश बिष्ट ने निर्वाचन साक्षरता क्लब को विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का सशक्त माध्यम बताया। जिला समन्वयक स्वीप विनोद कुमार राठौड़ ने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची, निष्पक्ष मतदान और निर्वाचन प्रक्रिया में जनभागीदारी लोकतंत्र की आधारशिला हैं। प्रतियोगिता के मूल्यांकन में पंकज जोशी, दीप प्रकाश जोशी, डॉ. प्रभाकर जोशी, प्रीति पंत, प्रदीप बिष्ट, मयंक तिवारी और रमेश रावत ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में दीपक पांडे, नीरज जोशी सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

'विकास में मैदान आगे, पहाड़ पीछे'...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

आजीविका की अपार संभावनाएं हैं। इसके बावजूद स्थानीय उत्पादों को बाजार, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल पाई है। परिणाम यह है कि पहाड़ का युवा रोजगार के लिए देहरादून, हल्द्वानी, दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे शहरों की ओर जाने को मजबूर है। पहाड़ में पैदा होने वाला श्रम मैदानों और दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, जबकि उसके अपने गांव खाली होते जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की फरवरी 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने भी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन के पीछे कमजोर आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा स्थानीय रोजगार की कमी को महत्वपूर्ण कारण बताया है।

पहाड़ की विकास संबंधी विडंबना शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अधिक स्पष्ट होती है। इंडियन एक्सप्रेस की नवंबर 2025 की एक पड़ताल के अनुसार, उत्तराखंड में 7,073 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम है। इनमें 1,740 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल एक शिक्षक है। 146 स्कूलों में सिर्फ एक विद्यार्थी दर्ज था, जिनमें 131 सरकारी स्कूल थे। स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। कैग के 2016 से 2021 के बीच के आडिट आंकड़ों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया कि चार मैदानी जिलों में विशेषज्ञ डाक्टरों के स्वीकृत पदों के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत कमी थी, जबकि नौ पर्वतीय जिलों में यह कमी लगभग 70 प्रतिशत थी।

यह कैसी विकास व्यवस्था है जहां स्कूल भवन बन रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं? अस्पतालों का ढांचा मौजूद है, लेकिन विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं? पहाड़ के लोगों को सामान्य इलाज के लिए भी देहरादून, हल्द्वानी या ऋषिकेश की दौड़ लगानी पड़ती है। इसका सीधा असर ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इलाज, शिक्षा और रोजगार के लिए होने वाला पलायन धीरे-धीरे स्थायी पलायन में बदल जाता है।

कैबिनेट बैठक में 23 फैसलों पर लगी..

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

रखरखाव से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य में कार्य नहीं करने के कारण एनएचआईडीसीएल को सूचीबद्धता से हटाने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड महाधिवक्ता सेवा अधिष्ठान कर्मचारी सेवा नियमावली को भी स्वीकृति मिली है।खनन विभाग के तहत जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शुल्क दर पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि खनन में बढ़ी हुई दरों के अनुरूप रॉयल्टी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ राजस्व कार्यपालक नियमावली तैयार करने के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति गठित की गई है। समिति की सिफारिशों के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही पंचम विधानसभा के सत्र का सत्रावसान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

न्याय की तलाश में परिवार की लड़ाई...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

लिया था। यह मामला पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर दर्ज हुआ था। गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब उन्हें अगले दिन सीबीआई से जुड़े मामले में अदालत के समक्ष उपस्थित होना था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। कथित वीआईपी से जुड़े आरोपों की जांच एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ उन आरोपों को सार्वजनिक करने वाले लोगों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इन मुकदमों की अपनी कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन क्या इससे मूल सवाल की जांच प्रभावित हो रही है? क्या सीबीआई इन सभी घटनाक्रमों को एक समग्र जांच के रूप में देख रही है?

मामले में सबसे नया और संवेदनशील मोड़ नवंबर 2026 में सामने आया। 16 नवंबर को पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य ने हरिद्वार में प्रेस कान्फ्रेंस कर अंकिता और उसके एक पुरुष मित्र के बीच कथित व्हाट्सऐप बातचीत के चार हजार से अधिक पन्ने सार्वजनिक किए। इन चौट के जरिए उन्होंने अपने बेटे की बेगुनाही का पक्ष रखने की कोशिश की। इसके बाद अंकिता के माता-पिता ने इसे अपनी मृत बेटी की निजता और गरिमा पर हमला बताते हुए पुलिस में शिकायत दी। उनका आरोप है कि उनकी बेटी की निजी बातचीत को सार्वजनिक कर उसकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की गई। 25 नवंबर को देहरादून के राजपुर थाने में विनोद आर्य और उनके अधिवक्ता अनुज पुंडीर के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की गई। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं 66सी और 66डी तथा भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और 79 का उल्लेख किया गया। बाद में अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामला हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया।

इस घटनाक्रम ने एक बार फिर अंकिता के परिवार को आहत किया है। जिस बेटी को न्याय दिलाने के लिए माता-पिता चार साल से संघर्ष कर रहे हैं, उसकी मृत्यु के बाद भी निजी जीवन की बातचीत सार्वजनिक विवाद का विषय बन गई है। सवाल यह भी है कि जांच के दौरान एकत्र किए गए इलेक्ट्रानिक साक्ष्य और निजी बातचीत को सार्वजनिक करने का अधिकार किसके पास है? क्या ऐसे संवेदनशील साक्ष्यों की सुरक्षा के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए?

अंकिता हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद मिलना न्यायिक प्रक्रिया की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन परिवार की पूरी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। चार साल में हत्याकांड से जुड़े मुकदमों और विवादों की फेहरिस्त लंबी होती गई है। कभी वीआईपी का सवाल, कभी आडियो-वीडियो की सत्यता, कभी गिरफ्तारी और अब मृत बेटी की निजी चौट सार्वजनिक करने का विवाद। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंकिता के माता-पिता को आखिर कब उन सभी सवालों के स्पष्ट जवाब मिलेंगे, जिनके साथ वह चार साल से जी रहे हैं? अंकिता को न्याय केवल सजा सुनाए जाने से नहीं, बल्कि हर अनुत्तरित सवाल का निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित जवाब मिलने से पूरा होगा।

दो लाख किसानों के खाते तक पहुंचेगा 600 करोड़!

हमारे संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में किसानों को सहकारी बैंकों के माध्यम से आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार दिसंबर महीने से प्रदेशभर में सहकारिता ऋण मेले आयोजित करने जा रही है। इन मेलों के जरिए करीब 2 लाख किसानों

◆उत्तराखंड में 1 दिसंबर से ऋण मेले का आयोजन



को लाभ पहुंचाने और 600 करोड़ रुपये तक का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 1 दिसंबर से प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में ऋण मेले आयोजित किए जाएंगे।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने नाबार्ड मुख्यालय में सहकारिता विभाग और नाबार्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में केंद्र सरकार से वित्तपोषित योजनाओं की प्रगति, ब्याजमुक्त ऋण वितरण, जिला सहकारी बैंकों के एनपीए, सहकारी संस्थाओं की आगामी एजीएम और विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता ऋण मेलों के आयोजन की तैयारियां समय से पूरी की जाएं। सभी 95 विकासखंडों में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने और किसानों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में जिला सहकारी बैंकों के एनपीए की स्थिति भी सामने आई। मंत्री ने अधिकारियों को एनपीए वसूली के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत करीब 400 करोड़ रुपये के एनपीए की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों से इस दिशा में गंभीरता से काम करने को कहा गया। सहकारिता विभाग की योजनाओं की जमीनी स्तर पर समीक्षा के लिए अपर निबंधक, संयुक्त निबंधक और उप निबंधक स्तर के अधिकारियों को जिलों में एमपैक्स स्तर पर बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और निर्देशों के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट 7 दिसंबर तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। सहकारिता मंत्री स्वयं 7 दिसंबर को समीक्षा बैठक कर योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे। बैठक में जिलों में ऋण वितरण की प्रगति भी सामने आई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, चमोली जिले ने ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य का 63 प्रतिशत हासिल किया है। उधम सिंह नगर में 52 प्रतिशत, अल्मोड़ा में 50 प्रतिशत, हरिद्वार में 49 प्रतिशत, पौड़ी गढ़वाल में 46 प्रतिशत, उत्तरकाशी में 43 प्रतिशत और देहरादून में 32.72 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया है। इसके अलावा, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत शून्य प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले अल्पकालीन ऋण वितरण की भी समीक्षा की गई। मध्यकालीन ऋण वितरण में पिथौरागढ़ ने 72 प्रतिशत, चमोली ने 65 प्रतिशत, नैनीताल ने 64 प्रतिशत, उत्तरकाशी ने 56 प्रतिशत, चंपावत ने 53 प्रतिशत और उधम सिंह नगर ने 52 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। वहीं, रुद्रप्रयाग में मध्यकालीन ऋण वितरण की उपलब्धि 43.34 प्रतिशत दर्ज की गई। सरकार की इस पहल के तहत दिसंबर में आयोजित होने वाले सहकारिता ऋण मेलों के जरिए किसानों तक ऋण सुविधा पहुंचाने और सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सिटीजन्स फॉर ग्रीन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से की मुलाकात

हमारे संवाददाता

देहरादून। उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) के आदेशों के अनुपालन में पर्यावरण संरक्षण संस्था 'सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून' के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ईरा चौहान, जया सिंह और हिमांशु अरोड़ा ने मुख्य सचिव से मुलाकात की। इस बैठक में मसूरी की वहन क्षमता को लेकर उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका और मसूरी को बचाने के लिए संस्था के सदस्यों व अनूप नौटियाल द्वारा दिए जाने वाले सुझावों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई।



वार्ता के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मसूरी और दून घाटी पर पड़ रहे अनावश्यक दबाव तथा अनियंत्रित पर्यटन पर गहरी चिंता व्यक्त की। संस्था के सदस्य हिमांशु अरोड़ा ने सवाल उठाया कि एक छोटे से हिल स्टेशन पर आखिर कितना दबाव डाला जा सकता है? उन्होंने चेताया कि यदि समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो मसूरी में भी जोशीमठ जैसी आपदा आने की पूरी आशंका है।

उन्होंने इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि मसूरी के लंढौर और झड़ीपानी जैसे क्षेत्रों में जमीन दरकने के मामले सामने आ चुके हैं, जो समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से प्रकाशित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने चिंताजनक आंकड़े रखते हुए बताया कि केवल पिछले 20 वर्षों में देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों (दून वैली) की करीब 47 प्रतिशत हरियाली नष्ट हो चुकी है। उन्होंने चेताया कि यदि बची हुई हरियाली को भी नहीं बचाया गया, तो हमारे शहर को मरुस्थल बनने से कोई नहीं बचा सकता।

ईरा चौहान ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नई मसूरी सड़क परियोजना पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि झाझरा से मिस्सरपट्टी होते हुए मसूरी जाने वाली इस नई सड़क के निर्माण में लगभग 18,000 से 20,000 पेड़ों की बलि चढ़ेगी, जिनमें मुख्य रूप से साल, रोहिणी, बुरांश और बांज के बहुमूल्य वृक्ष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त एलकेडी रोड के चौड़ीकरण में भी लगभग 700 पेड़ काटे जाने हैं, जिसे उन्होंने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

ईरा चौहान ने चेताते हुए कहा कि इस तरह के अनियोजित विकास से हम खुलेआम आपदाओं को निमंत्रण दे रहे हैं।

जया सिंह ने मसूरी की बुनियादी ढांचे की सीमाओं को रेखांकित करते हुए पूछा कि बढ़ते दबाव के बीच वहां की सीवेज व्यवस्था और पानी की किल्लत से कैसे निपटा जाएगा? उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पूरे मसूरी में केवल 1,287 वाहनों की पार्किंग की क्षमता है, ऐसे में वहां हजारों गाड़ियां भेजने का क्या औचित्य है? प्रतिनिधि मंडल की इन चिंताओं के जवाब में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार किसी को भी किसी शहर में आने से नहीं रोक सकती, क्योंकि निर्बाध आवागमन प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधि कार है और भारत का हर नागरिक कहीं भी आ-जा सकता है।

‘रफ्तार’ के पीछे अपराध का ‘नेटवर्क’

◆ऑनलाइन डिलीवरी की आड़ में नशे की तस्करी, चोरी, रेकी और नियमों की अनदेखी के मामले आए सामने

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। घर बैठे खाना मंगाना हो, किराने का सामान चाहिए हो या मोबाइल पर क्लिक करते ही रोजमर्रा की जरूरत की कोई वस्तु दरवाजे तक पहुंचानी हो, आनलाइन डिलीवरी सेवाओं ने जिंदगी को बेहद आसान बना दिया है। जेमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो और बिगबास्केट जैसी कंपनियों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। देहरादून में भी इन कंपनियों की सेवाएं शहर के बड़े हिस्से तक पहुंच चुकी हैं। सुविधा की इस चमकदार दुनिया के पीछे एक ऐसा सवाल भी खड़ा हो रहा है, जिसे नजरअंदाज करना अब मुश्किल है। आखिर इन कंपनियों के नाम पर घरों, गलियों, कालोनियों और प्रतिष्ठानों तक पहुंचने वाले लोगों की पहचान, पृष्ठभूमि और गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है? जिस डिलीवरी नेटवर्क पर लोग आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं, क्या उसकी हर कड़ी उतनी ही सुरक्षित है?

आनलाइन डिलीवरी का कारोबार केवल सामान पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गया है। इसके साथ एक बड़ा अनौपचारिक कार्यबल, तेज रफ्तार में चलने वाला परिवहन तंत्र और शहर के लगभग हर हिस्से तक पहुंच बनाने वाला नेटवर्क भी खड़ा हो गया है। यही नेटवर्क कुछ आपराधिक तत्वों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। देहरादून में सामने आए मामले इस आशंका को महज कल्पना नहीं रहने देते। देहरादून में 2022 में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया था, जिसमें आनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़े दो युवक नशे की सप्लाई कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक, आरोपी उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर देहरादून में इसकी आपूर्ति करते थे। डिलीवरी एजेंट होने का फायदा उठाकर वह पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश करते थे। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में नशे की कमाई से वाहन और जमीन खरीदने की बात भी सामने आई थी। यह मामला इसलिए गंभीर था क्योंकि अपराधियों ने आम लोगों के भरोसे से जुड़े एक पेशे को अपनी गतिविधियों की आड़ बनाया था।

मामला यहीं नहीं रुका। दिसंबर 2025 में देहरादून पुलिस ने रायवाला क्षेत्र में नशीले पदार्थों के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो डिलीवरी एजेंट बताए गए। पुलिस के अनुसार, आरोपियों से 31.94 ग्राम स्मैक और 158 ग्राम चरस बरामद हुई थी। इसी कार्रवाई से जुड़े एक अन्य मामले में एक डिलीवरी एजेंट पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक, वह सामान की डिलीवरी करते समय दुकानों और घरों की रेकी करता था। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल आपराधिक गतिविधियों के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि, इन घटनाओं के आधार पर पूरे डिलीवरी कार्यबल को संदेह के दायरे में रखना भी उचित नहीं होगा।

जुलाई 2023 में देहरादून पुलिस को शिकायतें मिली थीं कि कुछ डिलीवरी एजेंट और कलेक्शन एजेंट अपने काम की आड़ में घरों और प्रतिष्ठानों की रेकी कर रहे हैं। पुलिस को आशंका थी कि इस तरह जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल चोरी, लूट और नकबजनी जैसी वारदातों में किया जा सकता है। इसके बाद तत्कालीन एसएसपी के निर्देश पर क्लेमेंटटाउन और राजपुर थाना पुलिस ने डिलीवरी कंपनियों के टीम लीडरों और करीब 40 डिलीवरी एजेंटों के साथ बैठक की थी। सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। यह घटना एक अहम सवाल खड़ा करती है। डिलीवरी एजेंट को घर का पता, पहुंचने का रास्ता, परिवार की दिनचर्या और कई बार घर में मौजूद लोगों की जानकारी तक मिल जाती है। यदि इस जानकारी का गलत इस्तेमाल हो तो उपभोक्ता की निजता और सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ सकती हैं।

आनलाइन कंपनियों के बीच कुछ ही मिनटों में सामान पहुंचाने की प्रतिस्पर्धा ने डिलीवरी व्यवस्था को भी दबाव में ला दिया है। समय पर सामान पहुंचाने की होड़ में तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और दस्तावेजों की कमी जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। जनवरी 2026 में देहरादून संभाग के परिवहन विभाग ने ब्लिंकिट, जेमेटो और स्विगी से जुड़े डिलीवरी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की थी। अभियान के दौरान 41 वाहनों के चालान किए गए और आठ वाहनों को सीज किया गया। परिवहन अधिकारियों के अनुसार, कुछ वाहन बिना वैध दस्तावेजों के चल रहे थे। कुछ चालकों के पास लाइसेंस नहीं था और कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। इससे पहले दिसंबर 2024 में परिवहन विभाग ने क्रिक कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर डिलीवरी कर्मचारियों पर तेज गति से सामान पहुंचाने का दबाव नहीं डालने की हिदायत दी थी। उस समय देहरादून में इन सेवाओं से जुड़े करीब दो हजार डिलीवरी कर्मचारियों के काम करने की जानकारी सामने आई थी। यानी कारोबार की तेजी का असर केवल उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध सड़क सुरक्षा और शहर की कानून व्यवस्था से भी है।

फरवरी 2026 में उत्तराखंड पुलिस ने किरायेदारों, घरेलू सहायकों, सुरक्षा कर्मचारियों और होम डिलीवरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों के सत्यापन को लेकर व्यापक अभियान के निर्देश दिए थे। पुलिस महानिदेशक ने ई-कामर्स और आनलाइन सेवाओं से जुड़े डिलीवरी एजेंटों की पहचान और पृष्ठभूमि की जांच को भी प्राथमिकता में रखा था। यह पहल बताती है कि पुलिस भी इस नेटवर्क से जुड़े सत्यापन के महत्व को समझ रही है। लेकिन सवाल यह है कि कंपनियों के पास काम करने वाले हर व्यक्ति का अद्यतन रिकॉर्ड कितना व्यवस्थित है? कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, किसी दूसरे नाम से काम शुरू कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान पर डिलीवरी करने लगता है तो उसकी जांच कौन करता है? कंपनियां अपने प्लेटफार्म पर उपभोक्ता का मोबाइल नंबर, पता और भुगतान संबंधी जानकारी जुटाती हैं। लेकिन उपभोक्ता को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति की पृष्ठभूमि के बारे में कितनी जानकारी उपलब्ध होती है? डिलीवरी के दौरान किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर कंपनी की जवाबदेही क्या है? इन सवालों पर स्पष्ट व्यवस्था और प्रभावी निगरानी की जरूरत है।

आखिर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि दस मिनट में सामान घर पहुंच रहा है या नहीं। सवाल यह भी है कि उस सामान के साथ घर के दरवाजे तक कौन पहुंच रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसके इरादों की जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुविधा की यह दौड़ कहीं देहरादून की सुरक्षा के लिए नई चुनौती न बन जाए, इसके लिए अब जवाबदेही तय करना जरूरी है।

दो आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर हुई सुनवाई

हमारे संवादाता

नैनीताल। हाईकोर्ट में आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई।

मामले में केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह भी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने जा रही है। केंद्र ने अनुरोध किया कि केंद्र और राज्य सरकार की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए 10 दिन बाद की तिथि निर्धारित की है।

मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से यह भी पूछा कि इस रैंक के कितने पद प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित हैं और कितने पद राज्य सरकार के अधीन स्थायी रूप से हैं। जवाब में बताया गया कि ऐसे 16 पद हैं, जिन पर अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केंद्र में भेजा जा सकता है। शेष पद राज्य सरकार के अधीन हैं। मामले के अनुसार, 2005 बैच की आईपीएस अधिकारी नीरू गर्ग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में उप महानिरीक्षक और 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण मोहन जोशी को सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति दी गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में 5 मार्च 2026 को आदेश जारी किए गए थे। इसके अगले दिन यानी 6 मार्च 2026 को उत्तराखंड सरकार ने दोनों अधिकारियों को कार्यमुक्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। अधिकारियों ने राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने किया सचिवालय कूच

संवाददाता

देहरादून। एसीपी की मांग को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने सचिवालय कूच किया। जिनको बैरकेडिंग लगाकर रोक दिया गया।



आज यहां एसीपी की मांग को लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए जहां से उन्होंने एसीपी (पदोन्नत वेतनमान) बहाली सयुक्त4 मोर्चा के बैनर तले सचिवालय के लिए कूच किया। जब वह सचिवालय के करीब पहुंचे तो पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद वह वहीं धरने पर बैठ गये। उनका कहना था कि एसीपी (पदोन्नत व`तनमान बहाली संयुक्त मोर्चा, उत्तराखण्ड के द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिए पूरे सेवाकाल में 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा के उपरोन्त 03 पदोन्नत वेतनमान दिये जाने की मांग पूर्व में की जा रही है। संयुक्त मोर्चा द्वारा उत्तराखण्ड सरकार/शासन स्तर पर समय-समय पर सम्पन्न विभिन्न बैठकों में यक मांग प्रमुखता से उठाई जाती रही है किन्तु अभी तक इस दिशा में कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि एसीपी (पदोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखण्ड के सदस्य जो प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत है के कुल कार्यरत कार्मिकों में से 15 प्रतिशत सदस्यों को पूरे सेवाकाल में प्रथम पदोन्नति तथा लगभग 5 प्रतिशत सदस्यों को द्वितीय पदोन्नति मिल जाती है, शेष कार्मिक लगभग 30 से 35 वर्ष की सेवा के उपरान्त एक भी पदोन्नति प्राप्त किये बिना ही सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं जो कि एसीपी (पदोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखण्ड के सदस्यों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि पांचवे वेतन आयोग तक राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की सुविधा के अन्तर्गत 8 एवं 19 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा 14 व 24 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान की सुविधा अनुमान्य की जाती थी एवं छठवें वेतन आयोग की अनुमान्यता लागू होने पर उत्तराखण्ड के राज्य कर्मियों को एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान के रूप में प्रदान किया जाता रहा है, किन्तु उक्त सुविधा सातवें वेतनमान के अन्तर्गत एक जनवरी 2027 से समाप्त करते हुए 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पर मात्र अगले स्तर का ग्रेडवेतन अनुमान्य किया जा रहा है। पदोन्नत वेतनमान बहाली हेतु चार नवम्बर 2026 को एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारियों के साथ शीघ्र एक बैठक कर प्रकरण पर सकारात्मक कार्यवाही करने की मांग की गयी है।

दो दुपहिया वाहन चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने दो स्थानों से दो दुपहिया वाहन चोरी कर लिये। पुलिस ने दोनों मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार खुडबुडा मौहल्ला निवासी कमलेश गोयल ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह किसी काम से कैनाट पैलेस गयी थी। उसने अपनी स्कूटी नटराज चौक पर खडी की थी। जब वह थोडी देर बाद वापस आयी तो उसकी स्कूटी अपने स्थान से गायब थी। वहीं पुष्कर मंदिर मार्ग निवासी अमन कपिल ने ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए अपनी स्कूटी कपिल सर्जिकल के सामने से चोरी होना बताया। पुलिस ने दोनों मुकदमें दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।